

जान बची सौ लाखों पाए



जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 के अंतर्गत :

जानकारी लेने के लिए आप :

- जानकारी लिखित में मांग सकते हैं {धारा 6(1)}
- दस्तावेजों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं {धारा 2(i)}

कैसे :

- हर सरकारी दफ्तर में PIO (पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफ़सर) नियुक्त हैं {धारा 5(1)}
- PIO को लिखित अर्जी सामान्य शुल्क के साथ देना होगा। अर्जी की प्राप्ति रसीद मिलेगी {धारा 6(1)}

➤ सामान्य जानकारी 30 दिनों के अन्दर मिल जानी चाहिए {धारा 7(1)}

➤ जानकारी पाने के लिये (फोटोकॉपी, सत्यापित नकल, दस्तावेजों का इंस्पेक्शन इत्यादि) अतिरिक्त शुल्क देना होगा {धारा 7(3)}

➤ गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले आवेदक को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है {धारा 7(5)}

जानकारी न मिले या गलत मिले तो आप :

- प्रथम अपील संबंधित विभाग के अपील अधिकारी (फ़स्ट एपिलेट अथॉरिटी) को भेजें {धारा 16(1)}

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे अहम् संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब यह खतरे में आ जाता है, तो जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ है? जेल में बंदियों के चिकित्सा के क्या प्रावधान हैं? जेल या थाने में बंदी की मृत्यु के कारण, इत्यादि। ऐसी जानकारी मिलने में देर से अंधेर हो सकता है। इसीलिए, जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 में भी इस अधिकार को प्राथमिकता दी गयी है। कानून की धारा 7 के अनुसार, जहाँ साधारण जानकारी 30 दिनों के अन्दर मिलनी चाहिए, वहाँ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी 48 घंटों के अन्दर मिल जानी चाहिए। ऐसी जानकारी लिखित में आप मांग सकते हैं:

- गिरफ्तारी से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज़
- रोज़नामचे की प्रति
- जेल में मेडिकल दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, इत्यादि

कई जानकारियों नोटिस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से सरकारी दफ्तर द्वारा स्वयं बतायी जानी चाहिए {धारा (4)(1)(b)}

कॉमन्वेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

बी-117, सर्वोदय एनक्लैव, द्वितीय तल, नई दिल्ली-110 017

पूर्णाभाष: 011-43180200 / 211, फैक्स: 011-26864688

ईमेल: info@humanrightsinitiative.org

वेबसाइट: www.humanrightsinitiative.org



स्थानीय संपर्क—

श्री बलविंदर सिंह

श्री रमण शर्मा

Hall No. 301, A2 South Block, Bahu Plaza, Jammu

दूरभाष: +91-9419195295, 9796811012

ईमेल: jkrtiact@gmail.com, balirti_social@yahoo.com



जानकारी का अधिकार – जीने का अधिकार जानकारी लेना हमारा मौलिक अधिकार – जानकारी देने के लिए सरकार ज़िम्मेदार